नईदुनिया

संक्षिप्त समाचार

कच्चे तेल में तेजी का असर! सेंसेक्स 1,352 अंक गिरकर बंद

मुंबई। 9 मार्च को भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई, जिसमें सेंसेक्स 1,352.74 अंक (1.71 प्रतिशत) गिरकर 77,566.16 पर और निफ्टी 422.40 अंक (1.73प्रतिशत) गिरकर 24,028.05 पर बंद हुआ। बाजार में गिरावट का कारण ऑटो और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों की कमजोर स्थिति रही। निफ्टी ऑटो में 4.10त्न, निफ्टी पीएसयू बैंक में 3.97प्रतिशत और निफ्टी मेटल में 2.60प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान लार्जकैप के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी गिरावट आई, और निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1,127.85 अंक (1.97प्रतिशत) गिरकर 56,265.50 पर बंद हुआ। इंडिया विक्स इंडेक्स में भी 17.50प्रतिशत की तेजी आई, जो इस बात का संकेत था कि बाजार में अधिक उतार-चढ़ाव हो रहा था। सेंसेक्स पैक में अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, एमएंडएम, एसबीआई, इंडिगो और टाटा स्टील जैसी प्रमुख कंपनियां नुकसान में रहीं। वहीं, सन फार्मा, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा ने हल्की बढ़त हासिल की। बाजार में यह गिरावट कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह से आई। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ब्रेंट क्रूड की कीमत में 26प्रतिशत तक वृद्धि के कारण यह 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। इसके अलावा, डॉलर के मजबूत होने से भारतीय रुपये में भी कमजोरी आई, जो भारतीय बाजार के लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन गई। इस गिरावट के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मार्केट कैप 8 लाख करोड़ रुपए घटकर 441 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो पहले 449 लाख करोड़ रुपए था।

31 मार्च तक पीपीएफ, एसएसवाई और एनपीएस में करें निवेश, टैक्स बचत का मौका

नई दिल्ली। अगर आप साल के अंत में टैक्स बचाने की योजना बना रहे हैं, तो मार्च का महीना आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। इस दौरान आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) और नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में निवेश करके न केवल भविष्य के लिए पैसा एकत्रित कर सकते हैं, बल्कि टैक्स बचत का भी लाभ उठा सकते हैं।

पीपीएफ में निवेश करके आप धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह लाभ केवल पुरानी टैक्स रिजीम के तहत ही मिलता है। नई टैक्स रिजीम में इस पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती। यदि आपने इस वित्त वर्ष में पीपीएफ में निवेश नहीं किया है, तो यह एक अच्छा मौका हो सकता है। ध्यान रखें कि पीपीएफ खाते को एक्टिव रखने के लिए न्यूनतम 500 रुपए का वार्षिक निवेश जरूरी है, अन्यथा खाता निष्क्रिय हो सकता है। यह योजना खासतौर पर उन अभिभावकों के लिए है जिनकी बेटी है। इस योजना में भी धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। इस खाते को एक्टिव रखने के लिए 250 रुपए का न्यूनतम वार्षिक निवेश जरूरी होता है। एनपीएस में निवेश करने पर आपको दो तरह से टैक्स छूट मिल सकती है। पहली, धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट, और दूसरी, धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट। इसके अलावा, यदि आप पुरानी टैक्स रिजीम का चयन करते हैं, तो नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान पर भी कर लाभ मिलता है, जो आपके मूल वेतन और महंगाई भत्ते का अधिकतम 14 प्रतिशत हो सकता है। एनपीएस के तहत निवेश करने के लिए प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम 1,000 रुपए जमा करना अनिवार्य होता है।

उद्यम पोर्टल पर 3.07 करोड़ महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्योग पंजीकृत

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज संसद में जानकारी दी कि उद्यम पोर्टल पर फरवरी 2026 तक 3.07 करोड़ से अधिक महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्योग पंजीकृत हैं। यह जानकारी लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। मंत्री ने कहा, उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) और उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 28 फरवरी 2026 तक पंजीकृत महिला नेतृत्व वाले उद्यमों की कुल संख्या 3,07,42,621 है। सरकार महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रही है, जिसमें प्रमुख योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना है। इस योजना के अंतर्गत, महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को 75 प्रतिशत के मुकाबले 90 प्रतिशत तक की बढ़ी हुई ऋण गारंटी कवरेज प्राप्त होती है। इसके साथ ही, उन्हें गारंटी शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट भी मिलती है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत महिला उद्यमियों को कौशल और उद्यमिता सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना में कारीगरों और शिल्पकारों को बुनियादी और उन्नत कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता पर पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। इसके अलावा, पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (एसएफयूआरटीआई) के तहत क्षमता निर्माण और डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत उत्पाद डिजाइन, विकास, सेमिनार, कार्यशालाएं और तकनीकी उन्नयन जैसी गतिविधियों को भी समर्थन दिया जाता है।

चावल, चीनी मजबूत, गेहूं नरम, दालों, खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव

नयी दिल्ली। घरेलू थोक जिंस बाजारों में सोमवार को चावल के औसत भाव बढ़ गये। चावल के साथ चीनी में तेजी रही, जबकि गेहूं में नरमी देखी गयी। दालों और खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा। औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत 103 रुपये बढ़कर 3,856 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी। गेहूं 44 रुपये टूटकर 2,810 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। आटा भी 62 रुपये सस्ता हुआ। दाल-दलहनों में तुअर दाल औसतन 161 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई। चना दाल की कीमत 126 रुपये और मसूर दाल की 118 रुपये बढ़ गयी। मूंग दाल 70 रुपये मजबूत हुई। वहीं, उड़द दाल 10 रुपये प्रति क्विंटल टूट गयी। विदेशों में मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का मई वायदा 203 रिंगिट चढ़कर 4,570 रिंगिट प्रति टन पर पहुंच गया। मई का अमेरिकी सोया तेल वायदा भी 2.78 प्रतिशत की बढ़त में 68.43 सेंट प्रति पौंड बोला गया। स्थानीय बाजारों में मूंगफली तेल की औसत कीमत 189 रुपये प्रति क्विंटल गिर गयी। पाम ऑयल 60 रुपये और सोया तेल 44 रुपये सस्ता हुआ। सूरजमुखी तेल 38 रुपये की गिरावट में रहा। सरसों तेल और वनस्पति की कीमत 72-72 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ी।

जर्मनी, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों के साथ भारत की साझेदारी अब व्यापार से बढ़कर रक्षा, ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्रों में भी मजबूत हो गई है

भारत बना यूरोपीय संघ का अहम रणनीतिक साझेदार, संबंधों में हुआ व्यापक विस्तार

- भारत और यूरोपीय संघ के संबंध अब व्यापार से बढ़कर रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं।
- जर्मनी, फ्रांस, इटली और फिनलैंड ने भारत के साथ उच्च स्तरीय बैठकें और समझौते किए हैं।
- अब यह साझेदारी तकनीकी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र तक फैल चुकी है।
- जर्मनी ने भारत को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक प्रमुख साझेदार के रूप में मान्यता दी है।

नई दिल्ली। भारत के जर्मनी और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ संबंध अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि वे रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हो गए हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था, तकनीक और इंडो-पैसिफिक (हिंद प्रशांत) क्षेत्र की स्थिरता जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए हैं।

इंडिया नैरेटिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, हाल के वर्षों में जर्मनी, फ्रांस, इटली, फिनलैंड और यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठकों और नए समझौतों ने यूरोप को भारत के लिए इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के बाद दूसरा बड़ा रणनीतिक क्षेत्र बना दिया है।

पहले भारत और यूरोप के रिश्ते मुख्य रूप से व्यापार, सहायता और प्रवासी भारतीयों से जुड़े मुद्दों तक सीमित थे, लेकिन अब यह संबंध तकनीकी सप्लाई चेन, रक्षा उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में संयुक्त सहयोग तक फैल गए हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों

में ब्रसेल्स ने भारत को वैश्विक स्थिरता बनाए रखने वाला महत्वपूर्ण देश और %ग्लोबल साउथ% की मजबूत आवाज के रूप में देखना शुरू किया है। इसका उदाहरण फरवरी 2025 में यूरोपीय आयोग के आयुक्तों के समूह का भारत दौरा है, जो पहली बार हुआ था।

इसके साथ ही यूरोप के कई बड़े देशों ने भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत किया है। फ्रांस ने भारत के साथ अपने रिश्तों को %स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप% का दर्जा दिया है। वहीं जर्मनी भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है।

इटली ने 2025 से 2029 के लिए संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना जारी की है, जबकि फिनलैंड ने 2026 की शुरुआत में उच्च स्तर की बैठकों के जरिए भारत के साथ अपने संबंध और मजबूत किए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, इससे एक ऐसा ढांचा तैयार हो रहा है जिसमें यूरोपीय संघ के स्तर पर व्यापार, डिजिटल और कनेक्टिविटी सहयोग और सदस्य देशों के स्तर पर रक्षा, उद्योग और तकनीकी सहयोग शामिल हैं। इससे भारत की आर्थिक वृद्धि और सुरक्षा के लक्ष्य को भी मदद मिलती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जर्मनी और भारत के संबंध पहले से आर्थिक सहयोग पर आधारित थे, लेकिन अब यह साझेदारी रणनीतिक उद्योग और हरित ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में बढ़ रही है।

जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के जनवरी 2026 में भारत दौरे को इस बात का संकेत माना गया कि जर्मनी अब भारत को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक प्रमुख साझेदार के रूप में देखता है, न कि केवल एक उभरते हुए बाजार के रूप में।

भारत के लिए जर्मनी की पूंजी और तकनीक चीन पर निर्भर सप्लाई चेन के जोखिम को कम करने और देश में मैन्युफैक्चरिंग तथा हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है।

भू-राजनीतिक तनावों के बीच साइबर सुरक्षा और परिचालन को मजबूत करें कंपनियां: नैसकॉम

नई दिल्ली। आईटी इंडस्ट्री के प्रमुख संगठन नैसकॉम ने सोमवार को अपने सदस्य कंपनियों को एक अहम सलाह जारी की है, जिसमें उन्होंने मध्य पूर्व में बढ़ रहे भू-राजनीतिक तनावों के बीच साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और परिचालन में लचीलापन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। नैसकॉम ने कहा कि वर्तमान में व्यापारिक गतिविधियां स्थिर हैं, लेकिन कंपनियां किसी भी संभावित व्यवधान से बचने के लिए आकस्मिक योजनाओं की समीक्षा कर रही हैं और वे लचीलापन के उपायों को बेहतर बना रही हैं। कई कंपनियों ने अपने क्षेत्रीय संचालन के लिए व्यवसाय निरंतरता योजनाओं को सक्रिय कर दिया है, ताकि किसी प्रकार के व्यवधान के दौरान सेवा वितरण बाधित न हो। संगठन कर्मचारियों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दे रहे हैं और प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही, वे घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। कंपनियां अब इस क्षेत्र में क्लाउड प्लेटफॉर्म और डेटा सेंटर की सुरक्षा को और मजबूत करने और वैकल्पिक बुनियादी ढांचे के विकल्पों का मूल्यांकन करने पर ध्यान दे रही हैं।

भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से कारोबार करना हुआ आसान, एनएसडब्ल्यूएस ने दी 8.29 लाख मंजूरियां

नई दिल्ली। भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म सिस्टम ने कारोबार शुरू करने और विस्तार करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बना दिया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को जानकारी दी कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस), गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) और एमसीए21 जैसे डिजिटल टूल्स की मदद से कई व्यापार प्रक्रियाएं अब और भी सरल हो गई हैं। सरकार के बयान के अनुसार, एनएसडब्ल्यूएस के माध्यम से अब तक 32 केंद्रीय विभागों और 32 राज्यों में 8,29,750 से अधिक मंजूरियां दी जा चुकी हैं, जिससे व्यवसायों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई सरकारी मंजूरियां प्राप्त करने में सहूलियत हुई है।

इसके अलावा, एमसीए21 प्रोजेक्ट ने भारत के कॉर्पोरेट सिस्टम में बड़ा बदलाव

किया है। यह एआई-आधारित डिजिटल पहल पारदर्शिता को बढ़ाती है और इसमें ई-स्क्रूटनी, ई-एडजुडिकेशन और ई-कंसल्टेशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 2021 से 2025 के बीच लगभग 3.84 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं।

उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ने भी एमएसएमई सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहां 12 फरवरी 2026 तक 7.71 करोड़ रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, और इसने लगभग 33.97 करोड़ रोजगारों को समर्थन दिया है। जीईएम प्लेटफॉर्म, जो महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स, और दिव्यांग उद्यमियों को बाजार से जोड़ता है, वित्त वर्ष 2026 तक 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर दर्ज कर चुका है। इसके ऑक्शन मॉड्यूल के तहत दिसंबर 2021 से नवंबर 2025 के बीच 2,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की नीलामी की गई।

भारत ने केंद्र और राज्य स्तर पर मंजूरी प्रक्रियाओं को एकीकृत करके प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है, जिससे व्यापार वातावरण पारदर्शी, तेज और भरोसेमंद बना है। इसके अतिरिक्त, परिवेश और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल जैसे अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किए गए हैं, जो पारदर्शिता बढ़ाने और लागत कम करने में मदद कर रहे हैं।

भारत में महिला को-फाउंडेड टेक स्टार्टअप्स को शुरुआती फंडिंग में 2025 में हुई 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी: रिपोर्ट

नई दिल्ली। भारत में महिला को-फाउंडेड टेक स्टार्टअप्स को मिलने वाली कुल फंडिंग में 2025 में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन शुरुआती चरण (अर्ली-स्टेज) में निवेश में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में अर्ली-स्टेज फंडिंग 533 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो 2024 के 478 मिलियन डॉलर से ज्यादा है। हालांकि, इस दौरान फंडिंग डील्स की संख्या में गिरावट आई और यह 93 से घटकर 79 रह गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के अधिग्रहण में भी वृद्धि हुई है। 2025 में 33 अधिग्रहण दर्ज किए गए, जबकि 2024 में यह संख्या केवल 12 थी।

ट्रैक्सन की वार्षिक फंडिंग रिपोर्ट के अनुसार, महिला-सह-संस्थापक स्टार्टअप्स ने 2025 में कुल 1 अरब डॉलर की इक्विटी फंडिंग हासिल की, जो 2024 के 1.1 अरब डॉलर से लगभग 12 प्रतिशत कम है। हालांकि, सीड-स्टेज फंडिंग में 24 प्रतिशत की गिरावट आई। 2025 में 311 राउंड में 261 मिलियन डॉलर जुटाए गए, जबकि 2024 में यह राशि 342 मिलियन डॉलर थी।

सोने और चांदी की कीमतें लगातार चौथे दिन घटी

नई दिल्ली,। सोने और चांदी की कीमत में सोमवार को गिरावट देखने को मिली। यह लगातार चौथा दिन है, जब दोनों कीमती धातुओं की कीमत में कमी आई है।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत मामूली रूप से 77 रुपए घटकर 1,58,674 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,58,751 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।

22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,416 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 1,45,345 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। 18 कैरेट सोने का दाम कम होकर 1,19,006 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,19,063 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

चांदी का दाम 667 रुपए कम होकर 2,60,056 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 2,60,723 रुपए प्रति किलो था। जानकारों के मुताबिक, सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट की वजह इजरायल-ईरान युद्ध के चलते महंगाई बढ़ने से ब्याज दरों में कमी की संभावना कम हो जाना है, जो अभी तक कीमती धातुओं की रैली के पीछे सबसे बड़ी कारण था।

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना कमजोरी के साथ 5,100 डॉलर प्रति औंस पास बना है। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है, जिसके कारण फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती को लेकर सर्तक हो सकता है। इसने कीमती धातुओं में तेजी की संभावना को सीमित कर दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में एमसीएक्स पर सोना 1,58,000 रुपए से लेकर 1,64,000 रुपए की रेंज में रह सकता है और वैश्विक घटनाक्रम ही सोने की चाल तय करेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। खबर लिखे जाने तक, कॉमेक्स पर सोना 0.79 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 5,117 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.21 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 84 डॉलर प्रति औंस पर था।

रिलायंस रिटेल ने खरीदा हिमालय के प्राकृतिक उत्पादों पर आधारित स्किनकेयर ब्रांड पहाड़ी लोकल

नयी दिल्ली। रिलायंस रिटेल ने भारतीय ब्यूटी और वेलनेस ब्रांड पहाड़ी लोकल और उसके कारोबार का अधिग्रहण किया है। यह ब्रांड हिमालयी क्षेत्र से प्राप्त प्राकृतिक सामग्री पर आधारित स्किनकेयर उत्पाद बनाता है। रिलायंस रिटेल का यह अधिग्रहण उनके ब्यूटी और पर्सनल केयर पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा और भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहाड़ी लोकल 2018 में स्थापित हुआ था और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के साथ काम करता है। ब्रांड के उत्पादों में खुबानी के बीज का तेल प्रमुख सामग्री के रूप में इस्तेमाल होता है। रिलायंस रिटेल ने इस अधिग्रहण के बाद भी %पहाड़ी लोकल% की संस्थापक टीम को बनाए रखने का ऐलान किया है, जो ब्रांड की रचनात्मक दिशा और उत्पाद विकास में सक्रिय भूमिका निभाती रहेगी। रिलायंस रिटेल ने कहा है कि वह अपने रिटेल नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस ब्रांड को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने की योजना बना रही है।

सरकार ने आरबीआई स्विच ऑक्शन में खरीदी 6,309 करोड़ रुपए की जी-सिक्योरिटीज

मुंबई। सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित एक स्विच ऑक्शन के माध्यम से 6,309 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सिक्योरिटीज) को वापस खरीद लिया है, इससे निकट अवधि में परिपक्व होने वाले बांडों को लंबी अवधि की प्रतिभूतियों से बदल दिया गया है ताकि अपने पुनर्भुगतान दायित्वों को अधिक सुचारू रूप से प्रबंधित किया जा सके।

सरकारी प्रतिभूतियां, जिन्हें आमतौर पर जी-सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाता है, सरकार द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किए गए ऋण साधन हैं।

ये साधन कम जोखिम वाले माने जाते हैं क्योंकि इन्हें सरकार की गारंटी प्राप्त होती है और ये आमतौर पर निवेशकों को निश्चित रिटर्न प्रदान करते हैं।

नीलामी के दौरान खरीदे गए बॉन्ड अगले वित्तीय वर्ष में परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियों का हिस्सा थे। इसके बदले में सरकार ने लंबी

अवधि की प्रतिभूतियां जारी की हैं। स्विच ऑक्शन के जरिए सरकार को परिपक्वता के करीब पहुंच चुके बॉन्डों को बाद में परिपक्व होने वाले बॉन्डों से बदलने की सुविधा मिलती है।

इससे ऋण भुगतान दायित्वों को लंबी अवधि में फैलाने में मदद मिलती है और निकट भविष्य में सरकार की वित्तीय स्थिति पर दबाव कम होता है।

यह लेटेस्ट ऑपरेशन फरवरी से आरबीआई द्वारा आयोजित चौथा स्विच ऑक्शन है। इससे पहले, आरबीआई इसी तरह की तीन नीलामी हो चुकी थीं, जिनके माध्यम से 98,591.701 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिभूतियां वापस खरीदी गईं। यह बदलाव अगले वित्तीय वर्ष में मोचन के दबाव को कम करने के उद्देश्य से किया गया है, जब लगभग 5.47 लाख करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड परिपक्व होने वाले हैं। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने पहले ही 17.2 लाख करोड़ रुपए के सकल बाजार उधार का बजट तैयार कर लिया है।

अल्पकालिक प्रतिभूतियों को दीर्घकालिक प्रतिभूतियों से बदलकर, सरकार अपने ऋण परिपक्वता प्रोफाइल को सुव्यवस्थित करने और भविष्य के पुनर्भुगतान को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने का प्रयास कर रही है।

स्पेशल खबर वित्त मंत्री ने बताया कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में हालिया वृद्धि का भारत की महंगाई पर सीमित प्रभाव पड़ेगा

भारत में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का फिलहाल महंगाई पर असर नहीं: वित्त मंत्री निर्मला

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का भारत की महंगाई पर फिलहाल कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।
- उन्होंने बताया कि कच्चे तेल की कीमतें फरवरी के अंत से बढ़कर 69.01 डॉलर से 80.16 डॉलर प्रति बैरल हो गईं।
- सीतारमण ने कहा कि भारत की महंगाई वर्तमान में ‘निम्नतम सीमा’ के करीब है, जिससे इसका असर कम होगा।
- आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतें 10त्न बढ़ने पर महंगाई 30 आधार अंक तक बढ़ सकती है।

नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का भारत में महंगाई की दर पर प्रभाव फिलहाल अधिक नहीं माना जा रहा है, क्योंकि देश की महंगाई निम्नतम सीमा के करीब है।

लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत द्वारा आयात किए जाने वाले कच्चे तेल की कीमत पिछले एक वर्ष से लगातार गिर रही थी, जब तक 28 फरवरी, 2026 को पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक संघर्ष शुरू नहीं हुए थे।

सीतारमण ने कहा, फरवरी के अंत से लेकर 2 मार्च, 2026 तक कच्चे तेल की कीमत (भारतीय बास्केट) 69.01 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 80.16 डॉलर प्रति बैरल हो गई। चूंकि भारत में महंगाई अपने निचले स्तर के करीब है, इसलिए फिलहाल महंगाई पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण होने का अनुमान नहीं है।

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल

द्वारा ईरान पर सैन्य हमले शुरू करने के बाद से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। अब यह युद्ध मध्य पूर्व क्षेत्र में भी फैल गया है, क्योंकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं।

एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरबीआई की अक्टूबर 2025 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि यदि कच्चे तेल की कीमतें आधारभूत अनुमानों से 10 प्रतिशत अधिक होती हैं, और घरेलू कीमतों पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है, तो महंगाई 30 आधार अंक तक बढ़ सकती है। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का महंगाई पर मध्यम अवधि का प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, वैश्विक मांग और आपूर्ति की स्थिति, मौद्रिक नीति का संचरण, सामान्य मुद्रास्फीति की स्थिति और अप्रत्यक्ष प्रभाव की सीमा शामिल हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई औसत खुदरा मुद्रास्फीति (महंगाई) 2023-24 में 5.4 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 4.6 प्रतिशत और 2025-26 (अप्रैल-जनवरी) में और घटकर 1.8 प्रतिशत हो गई।

जनवरी 2026 के लिए मुख्य मुद्रास्फीति दर 2.75 प्रतिशत रही, जो आरबीआई के मुद्रास्फीति सहनशीलता बैंड (4 प्रतिशत से 2 प्रतिशत) की निचली सीमा के करीब है।

सीतारमण ने कहा कि मुद्रास्फीति प्रबंधन के तहत, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने फरवरी 2025 से अब तक नीतिगत दर में संचयी रूप से 125 आधार अंक की कमी की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आम नागरिक पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए कई उपाय भी किए हैं। इनमें आवश्यक खाद्य पदार्थों के लिए बफर स्टॉक बढ़ाना, खुले बाजार में खरीदे गए अनाज की रणनीतिक बिक्री, आयात को सुगम बनाना और आपूर्ति की कमी के समय निर्यात पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।

इसके अलावा, सरकार ने 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय (और वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 12.75 लाख रुपए तक) को आयकर से छूट देने जैसे राजकोषीय कदम उठाए हैं ताकि मध्यम वर्ग के पास अधिक पैसा हो। साथ ही, उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं को सस्ता बनाने के लिए जीएसटी दरों में भी कटौती की गई है।